भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2154
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2025

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना

2154. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या संचार **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मोबाइल टावर लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ख) सरकार द्वारा देश के उन गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जहां वर्तमान में नेटवर्क कवरेज नहीं है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्तपोषित स्कीम की योजना सरकार द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों सहित देश के सेवा से वंचित गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई गई है:

i. सेवा से वंचित 354 गांव स्कीम।
ii. आकांक्षी जिला स्कीम के सेवा से वंचित 502 गांव।
iii. आकांक्षी जिला स्कीम के सेवा से वंचित 7287 गांव।
iv. मेघालय के सेवा से वंचित और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर स्थित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान।

v. अरुणाचल प्रदेश और असम के दो (2) जिलों (कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ) के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान।

vi. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेवा से वंचित और राष्ट्रीय राजमार्ग -4 पर स्थित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान।

vii. लक्षद्वीप द्वीप समूह में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान और ओएफसी नेटवर्क का विस्तार।

viii. एलडब्ल्यूई चरण-I परियोजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित टावर वाले स्थानों पर 2जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। इस परियोजना के तहत स्थापित 2जी साइटों को 4जी में अपग्रेड किया जा रहा है।

ix. वामपंथी उग्रवाद चरण-II परियोजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित टावर स्थानों पर 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान।

x. 4जी सेचुरेशन स्कीम।

*****